Title: Need to review the functioning of FCI and Public Distribution System in the country- Laid.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, लगभग तीन साल की प्रतीक्षा के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद द्वारा भारतीय खाद्य निगम के ढांचे और उसके कार्यकरण में व्यापक सुधार के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अपार खाद्यान्न के भंडारों की उपलब्धता के बावजूद देश में कुपोाण और भूख से मौतें होने के समाचार हैं। गत् वर्ो में किसानों से 5 रूपया से 6 रूपया प्रति किलो गेहूं खरीदा गया, किंतु इस गेहूं का आर्थिक लागत मूल्य भारतीय खाद्य निगम को 9 रूपया प्रति किलो तक पहुंच गया। सरकार की सब्सिडी गत 4,5 वर्ो से 6 हजार करोड़ रूपये से बढ़कर 21 हजार करोड रूपया तक पहुंच चुकी है। अभी हाल ही में सरकार को एक सरकारी कार्य दल की रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। अतः इसमें व्यापक सुधार की जरूरत है। भारतीय खाद्य निगम हो या सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोनों कुप्रबंध के कारण अनुपयोगी बन चुके हैं, ऐसे हालात में सरकार द्वारा इस व्यवस्था के द्वारा अन्त्योदय योजना का विस्तार कर उसके माध्यम से और अन्न का वितरण बढ़ाने का निर्णय कारगर नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सबसे पहले उपरोक्त व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उसके बाद में इसमें विस्तार करने से उद्देश्य पूरा संभव है। अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि अविलम्ब भारतीय खाद्य निगम व सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त दुरूस्त बनाने के लिए ठोस प्रयास किये जायें।